न्यूज डायरी

बोरिस जॉनसन ने कहा, ब्रेक्जिट तभी चर्चा जब 12 दिसंबर को हों आम चुनाव

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज) लंदन। यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा है कि अगर सांसद 12 दिसंबर को मध्यावधि चुनाव कराने को तैयार हों तो वह ब्रेक्जिट विधेयक पर बात करने को तैयार हैं। 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर कैबिनेट की बैठक के बाद यह बात सामने आई। बता दें कि अभी 31 अक्टूबर ब्रेक्जिट की समय सीमा है लेकिन शुक्रवार को इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। बोरिस के सामने ब्रेक्जिट के लिए अल्पमत सरकार आड़े आ रही है। उन्हें सदन में बहुमत नहीं हासिल है। बोरिस जॉनसन ने कहा, अगर सांसदों को इस पर शोध करने के लिए समय चाहिए तो मैं तैयार हूं लेकिन यह समय तभी मिल सकता है जब वे 12 दिसंबर को आम चुनाव कराने के लिए राजी हों। उन्होंने आगे कहा कि यह लोगों के भले में है इसलिए विपक्ष को साथ देना चाहिए। जॉनसन ने पहले अक्टूबर में ब्रेक्जिट का वादा किया था लेकिन संसद में कम वोट मिलने की वजह से वह इसे पूरा नहीं कर पाए।

पाक ने 'संघर्ष विराम उल्लंघन' को लेकर भारतीय उप उच्चायुक्त को तलब किया

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज) इस्लामाबाद। पाकिस्तान ने भारत के उप उच्चायुक्त गौरव अहलूवालिया को शुक्रवार को तलब किया और नियंत्रण रेखा पर ''बिना उकसावे के संघर्ष विराम उल्लंघन'' की निंदा की। महानिदेशक मोहम्मद फैसल ने अहलूवालिया से कहा कि भारत के संघर्ष विराम का उल्लंघन क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के लिए एक खतरा है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत ने ''24 अक्टूबर को शाहकोट और खुईरट्टा सेक्टरों में बिना उकसावे के संघर्ष विराम का उल्लंघन किया और भारतीय सेना की बिना उकसावे के गोलीबारी के कारण तीन निर्दोष नागरिकों की मौत हो गई और एक घायल हो गया।'' जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधानों को हटाये जाने और राज्य को दो केन्द्र शासित प्रदेशों में बांटे जाने संबंधी भारत के फैसले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है।

बोलीवियाः विवादों के बीच इवो मोरालेस ने किया जीत का दावा

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज) ला पाज। बोलीविया के राष्ट्रपति इवो मोरालेस ने देश में रविवार को हुए आम चुनावों में अपनी जीत की घोषणा की। इन चुनाव परिणामों के बाद देश में दंगे भड़क गए और विपक्ष ने आरोप लगाया है कि वामपंथी नेता लगातार चौथा कार्यकाल हथियाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके कुछ ही घंटों बाद 'सुप्रीम इलेक्टोरल ट्राइब्यूनल' ने अपनी वेबसाइट पर मोरालेस को विजेता घोषित किया। ट्राइब्यूनल के अनुसार मोरालेस को 47.1 प्रतिशत मत मिले जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी कार्लोस मेसा ने 36.5 प्रतिशत वोट हासिल किए। मतगणना की प्रक्रिया को लेकर टीएसई की भारी आलोचना हो रही है। देश के उपराष्ट्रपति ने भी इसकी आलोचना करते हुए इस्तीफा दे दिया है। मोरालेस ने बृहस्पतिवार को संवाददाता सम्मेलन में कहा, 'हमने पहला चरण जीत लिया।'

द्वीप को पट्टे पर लेने की कोशिश न करे चीनी कंपनीः सोलोमन द्वीप

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज) होनियारा। सोलोमन द्वीप ने शुक्रवार को कहा कि उसके एक पूरे द्वीप को पट्टे पर लेने की एक चीनी कंपनी की कोशिश गैरकानूनी है और उसे ऐसा नहीं करने दिया जाएगा। सोलोमन द्वीप के प्रधानमंत्री मानाशेह दामुकाना सोगावर के कार्यालय ने एक बयान में कहा कि सोलोमन के सेंट्रल प्रोविंस और सरकारी 'चाइना सैम ग्रुप' के बीच हुआ समझौता गैरकानूनी है, इसे लागू नहीं किया जा सकता और तत्काल प्रभाव से इसे समाप्त किया जाना चाहिए।' बयान में बताया गया कि प्रांतीय सरकार के पास तुलागी द्वीप के संबंध में समझौते पर बात करने अधिकार नहीं है। इसमें बताया गया कि इसके अलावा, चाइना सैम के पास सोलोमन द्वीप में विदेशी निवेशक का दर्जा नहीं है और अटॉर्नी जनरल जॉन मुरिया की स्वीकृति के बिना कोई समझौता नहीं हो सकता। बयान में कहा गया है कि समझौते पर हस्ताक्षर से पहले अटॉर्नी जनरल के चौम्बरों ने इसकी जांच नहीं की थी।

शांति वार्ता आतंकवाद के खिलाफ इस्लामाबाद के कदमों पर निर्भर करती है: अमेरिका

भारत के साथ बातचीत की शुरुआत पाकिस्तान पर निर्भर करती है

चेतावनी

- एक हफ्ते के अंदर पाकिस्तान को अमेरिका से दो बार चेतावनी मिल चुकी है
- पाकिस्तान को आतंकवाद पर ठोस कार्रवाई करनी ही होगी

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

वॉशिंगटन। अमेरिका के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच शांति वार्ता की बहाली इस्लामाबाद के आतंकवादी संगठनों के खिलाफ उठाए निरंतर और स्थायी कार्रवाइयों पर निर्भर करती है। अधिकारी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के कश्मीर मामले पर भारत–पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करने को इच्छुक होने की बात भी दोहराई।

इसी हफ्ते एलिस वेल्स ने भी दी थी चेतावनीः इसी हफ्ते दक्षिण एवं मध्य एशिया मामलों की अमेरिकी कार्यवाहक सहायक विदेश मंत्री एलिस जी वेल्स ने भी कहा था कि

भारत–पाकिस्तान के बीच वार्ता की राह की मुख्य बाधा सीमा पार आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने वाले आतंकवादी समूहों को पाकिस्तान का समर्थन देना है।

उन्होंने कहा, श्उपयोगी द्विपक्षीय वार्ता फिर शुरू करने के लिए भरोसा कायम करने की आवश्यकता है और सीमा पार आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने वाले आतंकवादी समूहों को पाकिस्तान का समर्थन देना इस वार्ता में मुख्य बाधा है।

पठानकोट अटैक के बाद से बंद है बातचीतः पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन के जनवरी 2016 में पठानकोट के वायुसेना अड्डे पर हमला करने के बाद से ही भारत ने इस्लामाबाद से हर तरह का संवाद रोक रखा है। भारत का कहना है कि आतंकवाद और वार्ता एकसाथ नहीं चल सकते। भारत सरकार के 5 अगस्त को जम्मू–कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान खत्म करने के बाद दोनों देशों के बीच संबंध और खराब हो गए।

भारत के इस कदम के बाद पाकिस्तान ने कूटनीतिक संबंध का स्तर गिरा दिया और भारत के उच्चायुक्त को निष्कासित कर दिया।

ट्रंप ने की मोदी–इमरान से बातरू अमेरिकी अधिकारीः विदेश मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि अमेरिका उस माहौल को बढ़ावा देता रहेगा जो भारत–पाकिस्तान के बीच रचनात्मक वार्ता का रास्ता तैयार करे। नाम उजागर ना करने की शर्त पर अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच कायम तनाव को लेकर चिंता जाहिर की है और इस बारे में सीधे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात भी की है।

इमरान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन फजल से संबंधित संगठन पर लगा बैन

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

इस्लामाबाद। पाकिस्तान ने अगले सप्ताह देश में व्यापक स्तर पर किए जा रहे प्रदर्शन को कमजोर करने के लिए फजल–उर रहमान के नेतृत्व वाले जेयूआई–एफ से संबद्ध एक छोटे संगठन को प्रतिबंधित कर दिया है। इसने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए धरने पर बैठने की योजना बनाई थी।

गृह मंत्रालय ने गुरुवार को एक अधिसूचना जारी करते हुए अंसार उल–इस्लाम को प्रतिबंधित करने की घोषणा की और कहा कि यह संगठन 'एक सैन्य संगठन के रूप में 31 अक्टूबर को सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कार्य करने में सक्षम है। गौरतलब है कि जमीयत उलेमा ए इस्लाम के प्रमुख मौलाना फजल–उर रहमान ने घोषणा की है कि वह 31 अक्टूबर को सरकार के खिलाफ इस्लामाबाद में प्रदर्शन करेंगे।

पीएमएल–एन, पीपीपी, एएनपी और पीकेएमएपी सहित सभी प्रमुख विपक्षी दलों ने 'आजादी मार्च' को अपना समर्थन देने की घोषणा की है। रहमान ने आरोप लगाया है कि जुलाई 2018 में हुए चुनाव में पाकिस्तान तहरीक–ए–इंसाफ पार्टी की मदद करने के लिए धांधली की गई थी। उन्होंने खान का इस्तीफा मांगा है।

नायडू ने ईरान, नेपाल और बांग्लादेश के नेताओं से की मुलाकात

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज) बाकू। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने गुट निरपेक्ष आंदोलन (एनएएम) के राष्ट्रों और सरकारों के प्रमुखों के 18वें सम्मेलन से पहले, शुक्रवार को ईरान, नेपाल और बांग्लादेश के नेताओं से मुलाकात की। एनएएम शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे नायडू का सम्मेलन स्थल पर पहुंचने पर अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव ने स्वागत किया। नायडू के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति ने शिखर सम्मेलन से अलग, ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी से मुलाकात की।

गुलालाई इस्माइल मामले में अमेरिका ने पाकिस्तान को दी चेतावनी

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

वॉशिंगटन। पाकिस्तान में सरकारी एजेंसियों के उत्पीड़न से परेशान पख्तून मानवाधिकार कार्यकर्ता गुलालाई इस्माइल के मामले में अमेरिका ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने कहा, हमें गुलालाई इस्माइल के परिवार के उत्पीड़न की चिंता है और उनके पिता को हिरासत में लिए जाने पर बेहद दुख है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान अपने नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा करे। पाकिस्तान को शांतिपूर्वक सभा करने और अपनी बात रखने की छूट देनी चाहिए।

बता दें कि पाकिस्तान ने कहा– मानवाधिकारों का रखे ध्यान

गुलालाई पर राजद्रोह का आरोप लगाया है और इसके बाद उन्हें अमेरिका भागना पड़ा। पाकिस्तान की एक अदालत ने गुलालाई के खिलाफ गैरजमानती वॉरंट भी जारी किया है। अदालत ने यह भी चेतावनी दी थी कि अगर वह 21 अक्टूबर तक अदालत में पेश नहीं हुईं तो उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया जाएगा। गुलालाई इस्माइल पाकिस्तान से रहस्यमय तरीके से गायब हो गईं और उन्होंने राजनैतिक शरण के लिए आवेदन किया है।

गुलालाई पाकिस्तान में पश्तून समुदाय के अधिकारों के लिए

आवाज उठाती रही हैं इसलिए वह पाकिस्तान सरकार के निशाने पर रहती हैं। उन्होंने श्अवेयर गर्ल्सश नाम का एनजीओ बनाया है जिसके माध्यम से वह महिलाओं को जागरूक करने का काम करती रहती हैं। पाकिस्तान सरकार का आरोप है कि वह सरकारी एजेंसियों को बदनाम करती हैं हालांकि गुलालाई ने इन बातों से इनकार किया है।

ब्राजील जाने के लिए भारतीयों को नहीं लेना होगा वीजा

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज) साओ पाउलो। ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो ने गुरुवार को कहा कि भारत के कारोबारियों को ब्राजील आने के लिए वीजा की जरूरत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि चीन और भारत के लोगों के लिए वीजा की जरूरतों को कम किए जाने का फैसला किया गया है। बता दें कि बोल्सोनारो वर्ष की शुरुआत में सत्ता में आए हैं और उन्होंने कई विकसित देशों के लिए वीजा की जरूरतों में कमी की है।

हाल ही में वह चीन के दौरे पर थे और उन्होंने घोषणा की कि विकासशील देशों के लिए भी उनकी नीतियों में विस्तार किया जाएगा। कुछ दिन पहले ही ब्राजील ने अमेरिका, कनाडा, जापान और ऑस्ट्रेलिया के पर्यटकों और कारोबारियों को वीजा में छूट दी थी। हालांकि उन देशों ने ब्राजील को ऐसी कोई छूट नहीं दी है। बता दें कि बोल्सोनारो को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने के वादों की वजह से जीत मिली थी। उन्होंने काफी अंतर से चुनाव जीता था। हालांकि वह नस्लवादी, समलैंगिक विरोधी और महिला विरोधी टिप्पणियों की वजह से अकसर चर्चा में रहते हैं।